संदर्भ

Finn, Daniel K. (2006). *The moral ecology of market: Assessing claims about markets and justice.* New York: Cambridge University Press.

Fukuyama, Francis (1992). *The end of history and the last man.* London: Penguin.

Piketty, Thomas (2014). *Capital in the twenty-first century*. Harvard: Harvard Business School Press.

Polanyi, Karl (2001). *The great transformation* (New edition, 'Foreword' by Joseph Stiglitz). Boston: Beacon Press.

Zelizer, Viviana A. (1989). 'The social meaning of money: Special monies', *American Journal of Sociology*, *95*(2), 342–77.

Zelizer, Viviana A. (2005). *The purchase of intimacy.* Princeton: Princeton University Press.

Zizek, Salvoj. (2009). *First as tragedy, then as farce.* London: Verso.

रवि रंजन
असिस्टेंट प्रोफ़ेसर, राजनीति विज्ञान विभाग
ज़ाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज, नई दिल्ली
ईमेल: ranjanr1@gmail.com

कृष्णामूर्ति श्रीनिवासन, *Population Concerns in India: Shifting Trends, Policies, and Programs,* **नई दिल्ली: सेज पब्लिकेशंस, 2017, पृष्ठ xviii+294, रु 850, आईएसबीएन 878-93-864-4614-5 (HB)**

DOI: 10.1177/2581654318787704

भारत में जनसंख्या की समस्या को विकास में बाधक तत्त्व के रूप में देखा जाता रहा है। क्षेत्रीय विभिन्नताओं एवं अन्य सामाजिक स्तरीकरण के कारणों से जनसंख्या से संबंधित कई मुद्दे विवाद का विषय रहे हैं। इस पुस्तक में पिछले सात दशकों में जनसंख्या समस्या के सरोकारों, बदलती दशाओं, नीतियों एवं कार्यक्रमों का विस्तृत विश्लेषण किया गया है। देश के जनसंख्या विषय के इतिहास के अध्ययन के लिये यह एक उत्तम पुस्तक है। इसमें भारत के परिवार नियोजन कार्यक्रम, इसके परिणामों तथा सफल अनुभवों का सामाजिक-जनांकिकीय विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व जनसंख्या आकार के सरोकार मूलतः प्रजननता एवं मृत्युक्रम के संदर्भ में थे। नव-माल्थसवाद की धारणाओं को ध्यान में रखते हुए, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए अकाल एवं महामारियों पर ध्यान दिया गया था। पुस्तक के द्वितीय एवं तृतीय अध्याय श्रीनिवासन की 1995 में प्रकाशित पुस्तक, 'रेग्यूलेटिंग रिप्रोडक्शन इन इन्डियाज़ पॉपूलेशन' के ही संशोधित वृतांत हैं। इन अध्यायों में 1952–1977 की अवधि के परिवार नियोजन/कल्याण कार्यक्रमों एवं तत्पश्चात के राष्ट्रीय आपातकाल (1975–77) की परिस्थितियों का विश्लेषण किया गया है। इसके उपरांत, 1977–1995 के उत्तर-आपातकालीन प्रतिघात (Post-Emergency Recoil) एवं पुर्नरूत्थान चरण (Recovery Phase) का विषद विवरण प्रस्तुत किया गया है। इस समीक्षित पुस्तक में 1996–2015 की अवधि के नवीन जनसंख्या तथ्य सम्मिलित किए गए हैं। इस प्रकार से

यह स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर अब तक के जनांकिकीय तथ्यों तथा संदर्भों का वैज्ञानिक विश्लेषण है। पुस्तक में जनसंख्या तथ्यों को प्रस्तुत करने के लिए 10 अध्याय, 65 सारणियाँ, 17 चित्र, जनसंख्या नीतियों एवं कार्यक्रमों से संबंधित 4 परिशिष्ट, विस्तृत ग्रंथसूची एवं सूचीपृष्ठ दिए गए हैं।

पिछले दो दशकों में भारत में तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या नीतियों, कार्यक्रमों एवं मुद्दों में आधारभूत परिवर्तन आए हैं। संयुक्त राष्ट्र के 1994 के जनसंख्या एवं विकास के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (ICPD) के उपरांत कार्यक्रमों को मानव अधिकारों, महिलाओं के अधिकारों तथा महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य की दृष्टि से क्रियान्वित किया जाने लगा। अतः जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ की चर्चा कम हो गई। पिछले 15 वर्षों (1991–2016) में, भारत की जनसंख्या में 44.4 करोड़ की वृद्धि हुई, अर्थात् जनसंख्या 84.6 करोड़ से बढ़कर 129.0 करोड़ हो गई। पिछली चौथाई-सदी में यह वृद्धि विश्व के किसी भी देश (चीन सहित) से अधिक है। चीन की जनसंख्या का आकार तो बड़ा है, लेकिन वृद्धि दर कम रही है। इस पुस्तक को जनसंख्या समस्या के दृष्टिकोणों, नीतियों के प्रकारों, विभिन्न परिस्थितियों के संदर्भ में उपयुक्त कार्यक्रमों, राजतंत्र एवं जन आकांक्षाओं के अध्ययन की दृष्टि से एक अभिलेख (दस्तावेज़) कहा जा सकता है।

भारत विभिन्न भाषाओं, विविधताओं एवं सामाजिक स्तरीकरण प्रयुक्त देश है। यहाँ प्रजातंत्र की महत्ता हर चुनाव उपरांत अधिक सशक्त प्रतीत होती है। फिर भी, दिनचर्या में संस्कृति का प्रमुख स्थान है। इसके द्वारा प्रजननता, विवाह, जेंडर एवं शिशु देखरेख के आयाम प्रभावित होते हैं। संस्कृति, प्रजननता, वैवाहिक संबंध तथा विवाह संस्था के स्थायित्व के प्रश्नों का विश्लेषण किया गया है। धर्म एवं जाति के आधार पर विवाह संपन्न होने के कारण विवाह की स्थिरता बनी रही है। ऐसे विश्लेषणों से यह पुस्तक समाजशास्त्रीय दृष्टि से भी उपयोगी है।

पुस्तक में जनांकिकीय तथ्यों द्वारा विभिन्न राज्यों की तुलनात्मक स्थिति प्रस्तुत की गई है। इस आधार पर जनसंख्या कार्यक्रमों एवं नीति निर्धारण की चुनौतियाँ स्पष्ट की गई हैं। इसके उपरांत भारत की अन्य देशों से तुलना की गई है। इस प्रकार से अति-विकसित देशों एवं विकासशील देशों के मध्य अंतरों को ज्ञात किया गया है। जनसंख्या की डगमगाती नीतियों एवं संयुक्त राष्ट्र तथा अन्य एजेंसियों द्वारा किए गए युक्तिपूर्वक कार्यक्रमों तथा योगदानों को दर्शाया गया है। अंत में, उपसंहार के रूप में, आगे का रास्ता दिखाते हुए प्रमुख जनसंख्या मुद्दों को उठाकर कई महत्त्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किये गए हैं।

श्रीनिवासन जाने माने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जनांकिकीय विशेषज्ञ हैं। वे अनेक पुस्तकों एवं लेखों के रचियता हैं। वे कई उच्च स्तरीय पदों पर आसीन रहे हैं। फिर भी, पुस्तक में निष्कर्षों के सामान्यीकरण एवं सिद्धान्त निरूपण से बचते रहे हैं। उनके अनुसार, ऐसे देश में जहां भाषा, धर्म, नृजातीयता, सांस्कृतिक मूल्यों, परंपरागत मानकों, सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियों में विशाल विजातीयता (heterogeneity) हो, वहां सामान्यीकरण से तुरन्त आलोचनाएं एवं विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। जनसंख्या समस्या के विश्लेषण में प्रजननता, मृत्युक्रम एवं प्रवास की प्रक्रियाओं का प्रभाव होता है। अट्ठारहवीं शताब्दी में यूरोप के कई देशों में निम्न सामाजिक-आर्थिक वर्गों द्वारा अन्य देशों में प्रवास के फलस्वरूप जनसंख्या दबाव एवं निर्धनता में कमी आई है। लेकिन, इस प्रकार

का विकल्प भारत के लिए उपलब्ध नहीं था, और आधुनिक युग में किसी भी देश में प्रयुक्त नहीं है। पुस्तक में कई रोचक तथ्य प्रस्तुत किये गए हैं। इसकी संरचना एवं प्रस्तुतीकरण सराहनीय है। सामाजिक वैज्ञानिकों, नीति-निर्धारकों एवं शोधकर्ताओं के लिये प्रस्तुत पुस्तक उपयोगी सिद्ध होगी।

मोहन आडवानी
निदेशक
पुनर्वास एवं विकास अध्ययन संस्थान, उदयपुर
ईमेल: mohan.advani@yahoo.co.in

Bheemaiah Krishnan Ravi, *Modern Media, Elections and Democracy*, नई दिल्ली: सेज पब्लिकेशंस, 2017, रू 795, आईएसबीएन 978-93-866-0237-4

DOI: 10.1177/2581654318787679

किसी लोकतांत्रिक देश की सबसे ख़ूबसूरत बात यह होती है कि वहां की न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका के साथ-साथ चौथा स्तंभ अर्थात मीडिया भी स्वतंत्र रूप से कार्य करता हो। उसकी कार्यप्रणाली न सिर्फ़ स्वतंत्र हो, बल्कि उसको अपनी ज़िम्मेदारी का भी बखूबी एहसास रहे। बैंगलुरू यूनिवर्सिटी में बतौर रजिस्ट्रार कार्यरत लेखक भीमैया कृष्णन रवि की इस पुस्तक में कुल 10 अध्याय हैं। इसके पहले अध्याय 'इलेक्शंस एंड मीडिया इन डेमोक्रेसी' में उल्लेखित है कि किसी भी समाज के लिए मीडिया की क्या भूमिका होती है। मीडिया का राजनीति से जुड़ाव और उसकी ज़िम्मेदारी का वर्णन है। लेखक ने कहा है कि न सिर्फ़ भारत में बल्कि कई दूसरे लोकतांत्रिक देशों में मीडिया कॉरपोरेट और राजनीति के मकड़जाल में फंसकर अपने मूलभूत कार्य से अलग हो गया है। हालाँकि, लेखक इसी अध्याय में 'लंकेश' और 'तहलका' जैसी पत्रिकाओं पर भी प्रकाश डालते हैं, और मीडिया की अच्छी तस्वीर भी दिखाने का प्रयास करते हैं। रवि एकेडमिक जगत में आने से पूर्व मेनस्ट्रीम पत्रकारिता से जुड़े रहे हैं, इसलिए उनकी लेखनी में फ़ील्ड रिपोर्टिंग की धार स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। इसी अध्याय में उन्होंने चुनाव में मीडिया की भूमिका जैसे कई अहम मुद्दों पर रोशनी डाली है। दूसरे अध्याय में, वर्णन है कि कैसे आधुनिक समाज में मीडिया का ग़लत ढंग से प्रयोग किया जा रहा है। 'मॉडर्न मीडिया और सोसाइटी' नामक इस अध्याय में उन्होंने बताया है कि बढ़ती राजनीतिक अर्थव्यवस्था मीडिया को दूषित करने के पीछे एक प्रमुख कारण है। इस कारण न सिर्फ़ मीडिया का स्वामित्व प्रभावित होता है, बल्कि मीडिया की पहुँच और सुगम्यता पर भी नकारात्मक असर पड़ता है। प्राइवेट मीडिया, पब्लिक मीडिया और कम्यूनिटी मीडिया किस तरह से अपने लिए राजस्व एकत्रित करते हैं, इस अध्याय में इन बिंदुओं पर भी रोशनी डाली गई है।

21वीं सदी में लोगों को शिक्षित करने के लिए सबसे उपयुक्त अगर कोई तरीका है, तो वह है- मीडिया साक्षरता। राव के अनुसार, मीडिया जनमत तैयार करता है, लोगों को जागरूक करता है, लेकिन अगर मीडिया दूषित हो जाए तो वह अपने इस कार्य को ईमानदारी पूर्वक नहीं कर सकता। अतः ज़रूरी है कि